BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 14th January 2015 | No. 1

चैम्बर की 87वीं वार्षिक आम सभा सम्पन्न

ओ. पी. साह चौथी बार बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष निर्वाचित

87वें वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी दायीं ओर क्रमशः नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं नवनिर्वाचित महामंत्री श्री ओम प्रकाश टीबड़ेवाल तथा बाँयीं ओर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारी सचिव श्री सुरेश राम।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 87 वीं वार्षिक आमसभा सोमवार दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई। इसमें श्री ओ. पी. साह सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी व श्री मधुकर नाथ बरेरिया चुने गए। वहीं, डॉ. रमेश गाँधी को कोषाध्यक्ष और श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल को महामंत्री निर्वाचित किया गया।

सभागार में उपस्थित माननीय सदस्यगण।

आम सभा को संबोधित करते चैम्बर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

आमसभा में श्री अजय कुमार, श्री आलोक कुमार पोद्दार, श्री अनिल पचीसिया, श्री अशोक कुमार, श्री दिलीप जैन, श्री हरीश राज, श्री जयदीप जैन, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री पवन अग्रवाल, श्री रामलाल खेतान, श्री रोहित सिंह, श्री संजय भरतिया, श्री सतीश बंका, श्री सुनील गुप्ता, श्री स्वदेश कुमार व श्री संतोष कुमार सत्र 2014-15 के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित हुए।

आमसभा में उद्योग, उर्जा, वैट, लेबर, कम्यूनिकेशन एंड आई.टी. रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट और सूचना का अधिकार विषयों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। नये अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने सभी सदस्यों को उन्हें पुनः अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए धन्यवाद देते हुए आश्वस्त किया कि उनकी पूरी टीम राज्य के व्यवसायियों व उद्यमियों के हित के लिए समर्पित रहेगी।

उन्होंने कहा "सबका साथ सबका विकास" की भावना से मै अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करूँगा।

हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर के प्रेस प्रतिनिधियों के साथ चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह के संवाद के अंश

उत्तर व दक्षिण बिहार को जोड़े बगैर नहीं होगा उद्योग का विकास : ओ. पी. साह

- **राज्य सरकार से आपकी क्या-क्या मांगें हैं?**

जवाब : उद्योग को बचाने के लिए सबसे पहले उत्तरी व दक्षिणी बिहार को आपस में जोड़ना होगा। सरकार से पहली मांग है कि जल्द से जल्द गांधी सेतु की मरम्मत कर इसे चालू कराएं। दीघा व मुंगेर ब्रिज भी जल्द शुरू हो। गांधी सेतु पर

भारी वाहनों के परिचालन बंद होने से उद्यमियों को नुकसान हो रहा है। सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। सरकार को जो नुकसान हो रहा है वही पैसा ब्रिज में लगा दिया जाए तो ब्रिज बन जाएगा।

- **इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को क्या करेंगे?**

जवाब : बिहार में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार के समक्ष बात रखेंगे क्योंकि इसी कारण निवेशक नहीं आ रहे।

- **नए उद्योग के लिए क्या योजना है?**

जवाब : बिहार के प्रति बैंकों का रवैया नकारात्मक है। निवेशक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हे शक की नजर से देखा जाता है। बैंकों का रवैया सकारात्मक नहीं होगा तो उद्योग लगाने में परेशानी होगी। राज्य में उद्योग युनिट को पुनर्जीवित कराने का प्रयास करेंगे।

- **स्वरोजगार के मसले पर क्या करेंगे?**

जवाब : स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम चला रहा है। इसे और मजबूती देना है।

- **आगे का एजेंडा क्या होगा?**

जवाब : व्यवसायियों, उद्योगपतियों की समस्या हल करना मेरा पहला दायित्व होगा। सरकारी कानून और औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतें ठीक करेंगे। टुरिज्म पॉलिसी व हेल्थ सेक्टर की नीति सरकार के विचाराधीन है, इसे लागू कराने का प्रयास करेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 30.12.2014)**

फूड प्रोसेसिंग और नए उद्योगों को गति देने की होगी कोशिश : साह

हर तरह के उद्योग के विकास और इनसे जुड़ीं समस्याओं को दूर करने के लिए चैम्बर हमेशा सक्रिय रहा है। अब इसकी बागडोर एक बार फिर ओ. पी. साह के हाथ में है। इससे पूर्व भी वे तीन बार (वर्ष 2003-04, 2007-08, 2011-12) चैम्बर के अध्यक्ष रह चुके हैं। जाहिर हे लंबा अनुभव के साथ ही उद्यमियों की समस्याओं से भी वे पूरी तरह से अवगत हैं। जानते हैं क्या होगी उनकी प्राथमिकता....

- **किस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने पर सर्वाधिक जोर होगा?**

हर तरह के उद्योगों के विकास पर जोर होगा। खाद्य प्रसंस्करण सबसे ऊपर रहेगा। बिहार में जो नए उद्योग शुरू हुए हैं, उनकी बाधाएं दूर करने की कोशिश करूँगा। मसलन-सीमेंट, डिटर्जेंट, खाद्य तेल, बिस्कुट उद्योग।

- **नए इंटरप्रेन्योर तैयार करने के लिए भी कुछ करेंगे?**

चैम्बर का कौशल विकास कार्यक्रम इसी साल फरवरी में शुरू हुआ है। अब तक कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेंहदी आदि का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सोमवार को 150 महिलाओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। कुछ नए ट्रेड भी शामिल किए जाएंगे।

- **उद्योग-व्यापार के विकास में सबसे बड़ी बाधा इस समय क्या है?**

गांधी सेतु की मरम्मत नहीं होने, दीघा पुल और मुंगरे पुल के निर्माण पूरा नहीं होने से बड़े वाहनों का परिचालन बाधित है। इससे बिहार दो भाग में बंट गया है। उद्योग और व्यापार चौपट हो रहा है। मेरा अनुमान है कि इससे वर्ष 2013-14 में ही बिहार सरकार को 2000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगा है।

- **निदान के लिए क्या करेंगे?**

हमारी मांग है कि तीनों पुल पर मालवाहक गड़ियों का सुचारू ढंग से परिचालन हो। बिहार सरकार अपने पैसे से इन पुलों को चालू करें। केन्द्र भी हर संभव मदद करे। चैम्बर का सबसे आधिक जोर इसी पर होगा। **(सभार : दैनिक जागरण, 30.12.2014)**

राज्य के विकास के लिए उत्तर बिहार से सीधी कनेक्टिविटी जरूरी : साह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज में छह साल तक अध्यक्ष की पारी संभाल चुके ओ. पी. साह एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। सोमवार को एजीएम की बैठक के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर से सीधी बात की।

- **आप बिहार में इंडस्ट्रीज के विकास की गति से कितने संतुष्ट हैं?**

साह : मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। बिहार में केंद्र और राज्य की योजनाओं का समय से क्रियान्वयन नहीं होने से इंडस्ट्रीज निराश है।

- **बतौर नए अध्यक्ष आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी?**

साह : बिहार की लाइफलाइन माने जानेवाले गांधी सेतु के पुनर्निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। उत्तर बिहार से पटना की सीधी कनेक्टिविटी होनी जरूरी है।

- **लंबे समय से बड़े वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन बाधित है। ऐसे में व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है।**

साह : उद्योग और व्यापार को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पुल निर्माण को राजनैतिक मुद्दा बना कर राज्य और केंद्र अपनी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर थोप रहे हैं। इससे सूबे में माहौल खराब हो गया है। इस कारण निवेशकों ने बिहार से कन्नी काट ली है। व्यापार में स्टील, सीमेंट और भारी उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के तमाम जिलों में उद्यमी जाने से कतराते हैं।

- **टैक्स कलेक्शन का ग्राफ गिर रहा है। इससे पता चलता है कि सूबे में व्यापार और उद्यम की रफ्तार धीमी हुई हैं।**

साह : बिलकुल सही। जब वाणिज्यिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाएगा तो वाणिज्य कर कलेक्शन तो गिरेगा ही। बिक्रमशिला, गांधी सेतु की हालत खराब है। दीघा सड़क पुल और कनेक्टिविटी भी लंबित है। क्वालिटी बिजली को लेकर अबतक कुछ नहीं हो सका है। ऐसे में कारोबार काफी पीछे चला गया है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 30.12.2014)

कॉमर्शियल टैक्स के मामले में हासिल हुई उपलब्धि : अग्रवाल

चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल कार्यकाल की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि उनके नेतृत्व में बीसीसीआई ने एक तरफ कॉमर्शियल टैक्स के मामले में उपलब्धि हासिल की। वहीं प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी बनी।

- **आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?**

जवाब : कॉमर्शियल टैक्स व उद्योग दोनों से सभी लोगों का सरोकार है। हमने अपने कार्यकाल में कॉमर्शियल टैक्स के विपत्र को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया। इसका नतीजा यह हुआ कि कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर महीने के हर दूसरे और चौथे बुधवार को शाम में चैम्बर के साथ बैठक करते हैं। यह फिक्स्ड मीटिंग है। इसमें समस्याओं पर खुलकर बात होती है और समाधान भी निकलता है।

- **सरकार का रवैया कैसा रहा?**

जवाब : मेरे कार्यकाल में बीसीसीआई की माँग पर ही प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी बनी। इंडस्ट्रियल इनसेटिव पॉलिसी 2011 की मिड टर्म रिव्यू की गई। कैबिनेट ने इसे पास भी किया। राजनीतिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कैबिनेट बनी। व्यवसायिक आयोग के गठन की भी अधिसूचना जारी की गई।

- **स्वरोजगार के क्षेत्र में कोई उपलब्धि?**

जवाब : मेरे कार्यकाल में चैम्बर में कौशल विकास केंद्र खोला गया। सिलाई, कढ़ाई, बैग आदि बनाने की ट्रेनिंग शुरू की गई। मेडिकल के क्षेत्र में मेदांता हॉस्पिटल का कैंप लगा। बिहार में हॉस्पिटल खोलने और जमीन देने के मसले पर भी मदद की बात कही गई। **(साभार : हिन्दुस्तान, 30.12.2014)**

ओ. पी. साह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की बधाई

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का पुन : अध्यक्ष चुने जाने पर ओ. पी. साह को बधाई दी है। श्री रजक ने आशा व्यक्त की है कि फूड प्रोसेसिंग के साथ-साथ नए उद्योगों को राज्य में स्थापित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और स्वरोजगार जैसे महत्वपूर्ण मामलों में साह सक्रिय भूमिका निभाएंगे। **(साभार : दैनिक जागरण, 31.12.2014)**

नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव की ओ. पी. साह को बधाई

नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव ने ओपी साह को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद पर पुन: चयनित होने पर बधाई दी है। साथ ही आशा व्यक्त किया है कि साह के अध्यक्ष बनने पर राज्य में व्यवसाय और उद्योग को बढावा मिलेगा। उधर, जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अरूण कुमार गुप्ता, मनोज सिन्हा काजू महानगर अध्यक्ष शशिकांत गुप्ता सहित मारुफगंज व्यवसायिक संघ के नेताओं ने श्री साह को बधाई देते हुए उम्मीद जतायी है कि बिहार के विकास में व्यवसायियों का योगदान और भी बढ़ेगा। साथ ही व्यापार और नये व्यवसाय के विकास में भी कारगर कदम उठाये जायेंगे। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 1.1.2015)**

ओ. पी. साह के अध्यक्ष बनने पर व्यवसायी खुश

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद संभालने पर व्यापारियों ने ओ. पी. साह को बधाई दी है।

पटना सिटी व्यापार मंडल के बैनर तले विकास मोर्चा व तेरापंथ युवा परिषद की संयुक्त बैठक टेढ़ी घाट में हुई। अध्यक्षता प्रदीप सिंह यादव ने की। मौके पर महासचिव अवधेश सिन्हा, भगवती मोदी, प्रकाश कोठारी, अरुण मिश्रा, नवलकिशोर राम, उदय राय, मो. मेराजउद्दीन, विनोद पटेल मौजूद थे। युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव विनोद यादव ने भी ओपी साह के अध्यक्ष बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे बिहार में उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा। इधर मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष संजीव देवड़ा अमित कानोडिया, सन्नी साह, विकेश अग्रवाल, संदीप कमलिया, दीपू वागला, विजय मित्तल, पाटलिपुत्र जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष धर्मचंद्र सरावगी, राजेश कमलिया, पुरुषोत्तम पोद्दार, शिवप्रसाद मोदी, देवकिशन राठी, मारवाड़ी मम्मेलन के अध्यक्ष ईश्वर गोयनका, सुशील पोद्दार ने भी बधाई दी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 31.12.2014)

चैम्बर राज्य में निवेश का वातावरण बनाएं : मुख्यमंत्री

माननीय मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनके साथ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ. पी. साह के नेतृत्व में चैम्बर के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने चैम्बर के नए पदाधिकारियों को नववर्ष की शुभकामना दी। कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरकार की चिंता व प्राथमिकताओं पर ध्यान दे। राज्य में निवेश का वातावरण बनाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश का अभी सबसे अच्छा समय है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने मुख्यमंत्री का ध्यान गंगा ब्रिज से संबंधित समस्याओं पर आकृष्ट कराया और बताया की गंगा ब्रिज के कारण व्यापारियों को कठिनाई तो हो ही रही है, साथ ही राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। पी. के. अग्रवाल, एस. के. पटवारी, मधुकर बरेरिया, ओ. पी. टिबड़ेवाल, डॉ. रमेश गांधी और शाशि मोहन भी मौजूद थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.1.2015)**

दीघा पुल चालू करने की माँग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से दीघा पहलेजा रेल सड़क पुल एवं मुंगेर रेल सह सड़क पुल को शीघ्र चालू करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। अध्यक्ष ओ० पी० साह ने कहा कि पिछले दिनों रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से भी इसके लिए आग्रह किया गया था। उनहोंने इस मामले में कहा था कि दीघा-पहलेजा पुल का कार्य पूरा हो गया है। संपर्क पथ बनाने का काम राज्य सरकार का है। इस दिशा में पहल होनी चाहिए। साह ने कहा है कि भारी वाहनों की आवाजाही रूकने से व्यवसाय ठहर गया है। गाँधी सेतु पर भी यह रोक है। मुख्यमंत्री का भी इस ओर ध्यान दिलाया गया है। इसका असर राज्य के राजस्व पर भी पड़ रहा है। वैट संग्रह का लक्ष्य नवम्बर 2014 के लिए 8675.66 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध वास्तविक वसूली 7439.79 करोड़ रुपये ही हुई। इस तरह से लक्ष्य से विभाग 1235. 87 करोड़ रुपये पीछे रह गया है। अगर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है, तो यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.1.2015)**

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण-पत्र वितरित

चैम्बर द्वारा स्थापित एवं संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 तक प्रशिक्षण प्राप्त 81 महिलाओं को चैम्बर की 87 वीं वार्षिक आम सभा में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। ध्यातव्य हो कि यह प्रशिक्षण केन्द्र चैम्बर में 8 फरवरी 2014 से स्थापित एवं संचालित है।

प्रशिक्षित महिला को प्रमाण पत्र प्रदान करते चैम्बर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। साथ में अन्य पदाधिकारीगण।

13वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में चैम्बर की सहभागिता

प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सम्मिलित बॉये से बिहार चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

गुजरात के गाँधीनगर में आयोजित 13वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ,सदस्य श्रीमती नीलम अग्रवाल एवं संगीता टिबड़ेवाल बिहार सरकार की ओर से गए हैं। पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने बताया कि कई देशों से आये उद्यमियों से मिलकर उन्हें बिहार आने का न्योता दिया जायेगा। बिहार में संभावित उद्योगों के लिए इस समारोह से क्या मदद मिल सकती है। हमारा ध्यान इस ओर भी है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री भीम सिंह अपनी पूरी टीम के साथ इस आयोजन में उपस्थित हैं। शुक्रवार दिनांक 9.1.2015 को यहाँ लगे बिहार स्टॉल का उद्घाटन होगा जो तरक्की के साथ ही परम्पराओं की झलक देगा। **(साभार : दैनिक जागरण, दिनांक- 09.01.2015)**

दवा व्यवसायी की हत्या पर दुख व्यक्त

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सीतामढ़ी के प्रमुख दवा व्यवसायी एवं सीतामढ़ी केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्रस एसोसिएशन के अध्यक्ष यतीन्द्र खेतान की हत्या पर गहरा दुख एवं क्षोभ व्यक्त किया है।

चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि स्व. खेतान सीतामढ़ी के अत्यन्त लोकप्रिय दवा व्यवसायी थे। उनकी इस प्रकार हत्या कर दिये जाने से राज्य के व्यवसायियों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। इस घटना से व्यवसायी समाज

अत्यन्त मर्माहत है। श्री साह ने कहा कि पुलिस महानिदेशक पी. के. ठाकुर से बात कर सारी घटना एवं व्यवसायियों की भावनाओं से भी उन्हें अवगत कराया। पुलिस महानिदेशक ने मामले में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि वे स्वयं इस मामले का अनुश्रवण करेंगे तथा इस कांड के उद्‌भेदन एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग को भी सक्रिय किया जायेगा। उनकी हर सम्भव कोशिश होगी कि इस कांड के अपराधी पकड़े जायें तथा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि श्री खेतान की जघन्य हत्या से व्यवसायी समाज में गलत संदेश गया है जिसका विपरीत असर राज्य के व्यापार एवं उद्योग पर पड़ेगा। **(साभार : आज, 3.1.2015)**

गांधी सेतु बचाने को आगे आएं कारोबारी : ओ. पी. साह

उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद् की 57 वीं आमसभा में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि गांधी सेतु की समस्या बड़ी है। इसके जीर्णोद्धार के लिए सूबे के कारोबारियों को एकजुट होना होगा। पटना में धरना देना होगा। हालांकि श्री साह ने यह भी कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 व फूड प्रोसेसिंग नीति 2013 सरकार की अच्छी योजना है।

इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबे के उद्योग विभाग के मंत्री भीम सिंह ने कहा कि उद्योगों के विकास से ही बिहार का आर्थिक विकास संभव है। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार की और बढ़ना चाहिए। सबको नौकरी मिलनी मुश्किल है। वैसे नौकरी का दायरा भी सीमित है। स्वरोजगार के बल पर ही चीन ने तरक्की किया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार उद्योग व कारोबारियों को बेहतर माहौल दे रही है। नीतीश कुमार ने विकास के लिए बेहतर माहौल बनाया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 22.12.2014)**

उद्योग जगत को उम्मीद : ओ. पी. साह

वर्ष 2015 में राज्य के उद्योग-व्यापार जगत के लोगों को काफी उम्मीदें बंधी हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह का का मानना है कि नए वर्ष में केंद्र व राज्य सरकार उद्योग जगत के लिए बचे काम को पूरा करेगी। उद्योग-व्यापार और वाणिज्यकर प्रणाली की नीतियों में सुधार होने के साथ सरकारी नीतियों में पारदर्शिता लाने की भी जरूरत है। सरकार बीते वर्ष जिन योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे सकी, वह इस नए वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की भी संभावना है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.1.2015)**

लोन नहीं देने वाले बैकों पर शुरू हुई कार्रवाई

लोन नहीं देने वाले बैकों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार सब्सिडी राशि खर्च नहीं करने वाले बैंकों से पैसा वापस ले रही है। डेयरी लोन नहीं देने वाले बैंक ब्लैकलिस्टेड होंगे।

पिछले दो वित्तीय वर्षों में विभाग ने गव्य विकास योजना के लिए करीब 100 करोड़ राशि की स्वीकृति दी थी। इनमें सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर को 7 करोड़, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटना को 10 करोड़, पंजाब नैशनल बैंक बुद्ध कॉलोनी पटना को 10 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया एग्जीबिशन रोड पटना को 10 करोड़, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक पटना को 5 करोड़, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर को 5 करोड़, बिहार ग्रामीण बैंक बेगूसराय को 5 करोड़ रुपए अनुदान राशि जमा की गई थी लेकिन इनमें अधिकतर बैंकों का प्रदर्शन कमजोर रहा। पंजाब नैशनल बैंक का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। पीएनबी ने कुल राशि का 83.10 प्रतिशत खर्च किया है। पीएनबी ने 10 करोड़ में से 8 करोड़ 31 लाख 2 हजार 344 रुपए सब्सिडी के रूप में वितरित किए। भारतीय स्टेट बैंक का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। एसबीआई ने सिर्फ 35 लाख 38 हजार 218 रूपए यानी कुल राशि का 3.3 प्रतिशत राशि खर्च किया है। पशुपालन मंत्री बैद्यनाथ सहनी ने कहा कि पीएनबी को छोड़कर अन्य बैंकों से जमा राशि सरकार वापस ले रही है। इन बैंकों में अब गव्य विकास योजना की राशि जमा नहीं होगी। राशि जिलाधिकारी के पास भेजी जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.1.2015)

नोट पुराने, अब जून तक बदले जायेंगे

अगर आपके पास 2005 से पहले के छपे हुए नोट हैं और आपने उन्हें अब तक बदला नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसे बदलने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2015 कर दी है। इससे पहले इसकी समय सीमा 1 जनवरी तक तय की गई थी। आरबीआई ने परिपत्र जारी करते हुए कहा कि महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट करीब एक दशक से परिचालन में हैं और 2005 से पहले के ज्यादातर नोट बाजार से वापस लिए जा चुके हैं। इस दौरान जो भी नोट बचे हैं, वे बदल लिए जाएंगे, उसके बाद इनके परिचालन को बंद करने का निर्णय लिया जाएगा।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.12.2014)

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

आदेश

वर्ष 2013-14 के वार्षिक विवरणी दिसम्बर माह में दाखिल करने के प्रावधान के निमित्त विभागीय सर्वर पर अतिरिक्त भार होने के कारण ऑन-लाईन विवरणियों के दाखिला में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप धारा (6) के प्रथम परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में विवरणी दाखिल करने की निर्दिष्ट तिथि 31 दिसम्बर, 2014 को वित्तीय वर्ष 2013-14 की विवरणी के लिए दिनांक 31.01. 2015 तक विस्तारित करते हैं।

2. विभागीय आदेश संख्या- 6029 दिनांक - 31.12.2014 को रद्द किया जाता है।

ह०/-

(डा. ई. एल. एस. एन. बाला प्रसाद)

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- बिक्री-कर/ विविध - 43/ 11- 6044 पटना, दिनांक- 31.12.2014

प्रतिलिपि -सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशसन/ अपील/ अंकेक्षण)/ सभी अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

औद्योगिक प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, बिहार, 2014

बिहार सरकार, उद्योग विभाग के संकल्प पत्रांक - 9 दिनाक 5.1.2015 के द्वारा राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो दिनांक 1.7.2011 से अगले पाँच वर्षों तक अर्थात दिनांक 30. 6. 2016 तक प्रभावी है। इस नीति के प्रावधान के अधीन मध्यावधि समीक्षा की गई जिसके आलोक में राज्य सरकार, बिहार एतद् द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संकल्प निर्गत करने की तिथि से कुछ संशोधन किया है।

विभाग से प्राप्त संकल्प की पूरी प्रति इमेल द्वारा सदस्यों की सेवा में प्रेषित की जा चुकी है यदि किसी सदस्य को इसकी प्रति की आवश्यकता हो तो चैम्बर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

वैट के साथ प्रवेश कर भी वापस होगा उद्यमियों को

राज्य के उद्योगों को अब प्रवेश कर के रूप में ली गई राशि सरकार वापस करेगी। वैट के साथ ही 300 प्रतिशत की सीमा के भीतर यह राशि होगी। उद्योग जगत की इस पुरानी मांग पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। पैसे की यह वापसी उद्योग के उत्पादन में आने के बाद की जाएगी। उनके द्वारा लिए गए टर्म लोन के ब्याज पर सरकार अनुदान भी देगी।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की मध्यावधि समीक्षा को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। नई नीति के अनुसार उद्योगपतियों को सूद पर दो प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। एससी-एसटी, महिला और निःशक्त उद्यामियों के लिए यह सीमा 5% की होगी। उद्योग लगाने पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पूंजीगत अनुदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए तक कर दी गई। समूह के रूप में एसवीपी बनाकर उद्योग लगाने पर यह सीमा 50 करोड़ की होगी। सरकार अनुदान के रूप में 35% राशि देती है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.12.2014)**

बिना परमिट के प्रवेश करने पर एफआईआर

वाणिज्य कर विभाग ने सोमवार को राज्य के सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को निर्देश दिया है कि अब एक भी ट्रक बिना परमिट के बिहार में प्रवेश करता है तो कार्रवाई बाद में होगी, पहले सीधे एफआईआर होगी। एफआईआर ट्रांसपोर्ट के मालिक, मैनेजर या गोदाम इंचार्ज किसी पर भी हो सकती है। इतना ही नहीं एफआईआर ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक के मालिकों पर भी होगी।

सोमवार को वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव सह आयुक्त ने राज्य के सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ बैठक की। बताया कि पिछले कुछ दिनों में लाख समझाने के बावजूद बिहार में बिना परमिट के सामान लगातार आ रहे हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.1.2015)

नए ट्रांसपोर्ट बिल का विरोध करेंगे ट्रांसपोर्टर

केंद्र सरकार के नए ट्रांसपोर्ट बिल का बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन विरोध करेगा। फेडरेशन का कहना है कि नए परिवहन बिल में ट्रांसपोर्टरों के हित में कुछ भी नहीं है। फेडरेशन ने नए प्रस्तावित बिल में कई कमियां गिनाई है। कहा कि नया बिल कॉरपोरेट घरानों के दबाव में लाया जा रहा है। नए बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन होगा।

बताया कि नए बिल में ट्रांसपोर्टरों पर केंद्र सरकार का दबदबा होगा और राज्य सरकार की शक्ति कम हो जाएगी। यही नहीं वाहनों के टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी जो छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय सिंह का कहना है कि यह सच है कि वाहन चालकों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए लेकिन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने व सजा का जो प्रावधान किया गया है वह अव्यवहारिक है।

नए बिल में सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत होने पर तीन लाख रुपए जुर्माना व सात साल जेल की सजा का प्रावधान है। शराब पीकर वाहन चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार दंड या जेल की सजा और 6 माह ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित रखा जा सकता है। अगर यही अपराध तीन वर्ष के अंदर दोबारा किया गया तो 50 हजार रुपए दंड व एक साल जेल की सजा और एक साल लाइसेंस निलंबित रखने का प्रावधान है। तीसरी बार ऐसा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। स्कूली बस के ड्राइवर वाहन चलाते वक्त शराब पीते पकड़े गए तो 50 हजार रुपए दंड व तीन साल की सजा का प्रावधान है। अगर ऐसे अपराध करने वाले ड्राइवर की उम्र 18 से 25 साल के बीच है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। नए बिल में नेशनल सेफ्टी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है। नए बिल के अनुसार बस चालक व पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। नहीं तो 5000 का पैनाल्टी होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.1.2015)

जीएसटी में पेट्रोलियम बाधा

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि वह पेट्रोलियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े मसलों को हल कर लेगी। कुछ साल पहले नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पेश की गई थी और नई सरकार को उम्मीद है कि यह 2016-17 से लागू हो जाएगा। अभी इसकी राह मुश्किल नजर आ रही है।

इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार को पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए 29 राज्यों में से 20 राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए लोक सभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, लेकिन इसमें राज्यों को इस पर मूल्यवर्धित कर (वैट) और उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। यह मध्य मार्ग है, क्योंकि राज्य सरकारें पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लगाना चाहतीं, क्योंकि इससे राज्यों को बड़ी धनराशि मिलती है।

यह व्यवस्था तब तक बनी रहेगी, जब तक जीएसटी परिषद इसमें बदलाव न कर दे। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 23 दिसम्बर को निम्न सदन में पेश किए गए विधेयक में कहा गया है, ' वस्तु एवं सेवाकर परिषद पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन पर जीएसटी लागू किए जाने की तिथि तय करेगी।' **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 31.12.2014)**

118 हजार करोड़ का होगा अगला बजट

तैयारी योजना आकार में 25 फीसदी व गैर योजना मद में 15 फीसदी वृद्धि की संभावना

पांच साल में दोगुना से ज्यादा हुआ बजट		तीन साल में बढ़ा योजना आकार	
2010-11	51 हजार करोड़	2012-13	28 हजार करोड़
2011-12	60 हजार करोड़	2013-14	31 हजार करोड़
2012-13	70 हजार करोड़	2014-15	40 हजार करोड़
2013-14	92 हजार करोड़	(केंद्रीय आवंटन मिला कर 57 हजार करोड़)	
2014-15	118 हजार करोड़		

राज्य का बजट आकार तेजी से बढ़ रहा है। चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष (2015-16) के बजट आकार में करीब 21 हजार करोड़ की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी लगभग 18 फीसदी है। इस वित्तीय वर्ष से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पैसे राज्य सरकार के खजाने में ही सीधे आने के कारण राज्य के योजना आकार में करीब 17 हजार करोड़ की बढोतरी हो गयी है। इस बार योजना मद में 25 फीसदी की बढोतरी होगी। यह 57 हजार करोड़ से बढ़ कर 71 हजार करोड़ रुपये होगा।

इसी तरह गैर-योजना मद में 15 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। यह 40 हजार करोड़ से बढ़ कर 47 हजार करोड़ रुपये हो जायेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के साथ बजट की तैयारी करने के लिए 17 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक मैराथन बैठक की। इस बैठक में विभागवार बजट से जुड़ी तमाम अहम बातों पर चर्चा हुई। तमाम विभागों से फीडबैक लेने के बाद अब वित्त विभाग नये बजट की रूपरेखा तैयार करने में पूरी तरह से जुट गया है। बजट का प्रारंभिक आकलन तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार, राज्य का आगामी बजट 118 करोड़ रुपये का होगा। हालांकि बजट को लेकर निर्णायक बैठक वित्त मंत्री विजेंद्र यादव की अध्यक्षता में 9, 12 और 13 जनवरी को सभी विभागों के साथ होगी। इस दौरान कई अहम बातों पर चर्चा होगी।

कई योजनाएं होंगी बंद : इसके अलावा सभी विभागों के अंतर्गत चल रही कुल 757 योजनाओं में कई योजनाओं को मर्जर या मिलाने या इन्हें बंद कर देने की तैयारी चल रही है। राज्य में करीब 87 ऐसी योजनाएं ऐसी हैं, जो कागज पर तो मौजूद है, लेकिन इनके लिए न कोई आवंटन मिला और न ही ये जमीन पर उतर पायी हैं। फाइलों में ही बंद पड़ी इन योजनाओं को बंद करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 6.1.2015)

बिजली टैरिफ पर पटना में जनसुनवाई 10 जनवरी और 3-4 फरवरी को

मौजूदा बिजली दरें

शहरी घरेलू

यूनिट	विद्युत दर
1-100	2.85 रु.
101-200	3.50 रु.
300 से अधिक	5.30 रु.

शहरी कॉमर्शियल

यूनिट	विद्युत दर
1-100	5.00 रु.
101-200	5.30 रु.
201 से अधिक	5.70 रु.

ग्रामीण क्षेत्र मीटर

यूनिट	विद्युत दर
1-50	2.00 रु.
51-100	2.30 रु.
100 से अधिक	2.70 रु.

बिजली टैरिफ पर पटना में 10 जनवरी और 3 व 4 फरवरी 2015 को जनसुनवाई की जाएगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पटना स्थित सभागार में सुनवाई होगी। इस क्रम में 7 जनवरी 2015 को भागलपुर में, 12 जनवरी 2015 को छपरा में, 19 जनवरी 2015 को दरभंगा में, 20 जनवरी 2015 को सहरसा में और 21 जनवरी 2015 पूर्णिया में भी रेग्यूलेटरी कमीशन जनसुनवाई करेगा।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा बिजली दरों में पचास फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेज दिया है। आयोग प्रदेश के कई प्रमंडलों में जन सुनवाई शुरू का चुका है। जनसुनवाई पूरी होने के बाद दरों को बढ़ाए जाने या नहीं बढ़ाने पर आयोग फैसला करेगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मौजूदा वर्ष में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसलिए कुटीर ज्योति जैसी सरकारी अनुदान वाले टैरिफ के स्लैब में बढोतरी की जा सकती है। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ नहीं पड़ सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में भी आयोग ने सरकारी अनुदान प्राप्त उक्त टैरिफ स्लैब में बृद्धि की थी, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ नहीं पड़ा। बिजली की दोनों वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए खुदरा बिजली की दरों में पचास फीसदी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें इनर्जी चार्ज, फिक्सड व मिसलेनियस चार्ज के अलावा न्यूनतम इनर्जी चार्ज व बीपीएल की बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर पटना समेत सूबे के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में जनसुनवाई हो रही है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.1.2015)

अब राजधानी में प्री-पेड बिजली

महीनों बिजली का बकाया न चुकाने वालों के लिए बुरी खबर है। तीन-चार दिनों में राजधानी में प्री-पेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड शुरुआत विद्युत बोर्ड कॉलोनी से

करने जा रही है। पहले इसे सरकारी आवासों में लगाया जाएगा। गैर सरकारी उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराने की योजना है। तर्क है कि इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। सरकारी आवास में जो रहेगा, उसे मीटर रीचार्ज कराना पड़ेगा। एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी को यह जिम्मेदारी मिली है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.1.2015)

घर बैठे बिजली बिल जमा करने की योजना फ्लॉप

घर बैठे बिजली बिल जमा करने की योजना धरातल पर नहीं उतर रही है। विद्युत कंपनी ने इस लोकप्रिय योजना पर बड़ी रकम खर्च की है। दूसरी तरफ कंपनी के अभियंता आलाधिकारियों की नाराजगी से बचने के लिए इसका दोष उपभोक्ताओं पर मढ़ रहे है। उनका कहना है कि पॉश मशीन से बिल भुगतान की एवज में जो 5-9 रुपये कमीशन लगता है, उपभोक्ता वह देने को तैयार नहीं हैं।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.1.2015)

फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण पर नजर

गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने कवायद तेज कर दी है। गंगा किनारे चलने वाली राज्य की 13 बड़ी औद्योगिक इकाइयों सहित छोटे-बड़े तीन दर्जन से अधिक उद्योगों को पर्षद ने 31 मार्च से पहले रियल टाइम इफ्यूलेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है। यह सिस्टम बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीधा जुड़ा होगा इसके अलावा राज्य की सभी बड़ी एवं छोटी औद्योगिक इकाइयों को डिस्प्ले बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया है, जो फैक्ट्री से निकलने वाले ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से दिखाएगा।

इसी रिपोर्ट पर आगे बढ़ेगा नमामि गंगे.... : औद्योगिक इकाइयों में लगने वाले रियल टाइम इफ्यूलैंट मॉनिटरिंग सिस्टम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सिस्टम जुड़ा होगा। फैक्ट्रियों से निकलकर नाले के माध्यम से गंगा में जाने वाले पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की पल-पल की रिपोर्ट भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी। इसी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद तेज की जाएगी।

ट्रिब्यूनल करेगा मॉनिटरिंग : गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अब तक किए गए उपायों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) कर रहा है। एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने गंगा के किनारों से जुड़े सभी राज्य की सरकारों को 31 मार्च से पहले प्रदूषण की मॉनिटरिंग करने के लिए मशीन लगाने का निर्देश जारी किया है।

"गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने कई उपाय किए हैं। पहले चरण में 31 मार्च तक रियल टाइम इफ्यूलेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण में गंगा में गिरने वाले नालों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। " – **नवीन कुमार**, वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

(सभार : दैनिक भास्कर, 7.1.2015)

Make Bihar part of India drive, Bihar urges Centre

Reminding Prime Minister Narendra Modi of his election promise, State Industries Minister Bhim Singh urged him to integrate Bihar as part of the Centre's "Make in India" campaign to pave way for rapid industrialisation of the state.

Singh said it was necessary that Bihar should be considered as an investment destination if the Centre want to achieve 25% industrialisation in the next 10 years vis-a-vis current rate of 15%.

The minister said he had to issue an appeal in the light the Central government's apathy towards construction of Amritsar-Delhi-Kolkata industrial corridor." This corridor passes through four Bihar districts like Kaimur, Rohtas, Aurangabad and Gaya. Ironically, this is one of the five such corridors, where even elementary work has not been started."

Claiming that the state has received investment proposals to the tune of Rs. 3,554 crore during the outgoing year, the minister said the government had announced many sops as part of the industrial incentive policy to promote industrialisation. He said the revised policy envisaged upto 300% reimbursement of Vat and entry tax on production of major industries.

Briefing salient features of the mid-term appraisal of the industrial incentive policy of 2011, the minister said the government had announced 2% grant on interest of term loan borrowed by industrial units. "Extra 5% grant on interest will be given to the entrepreneurs, if they belong to SC/ST, women or handicapped persons," said Singh.

The minister said the department is contemplating to bolster the single window system to facilitate investment proposals by ensuring presence of at least six & seven officers from different related departments.

The department has also initiated the work to build a tool room-cum-training centre in Patliputra industrial area, for which the state government has allocated Rs.11.57 crore for land acquisition. Besides, 25-acre land has been earmarked for establishment of a fragrance and flavour centre by the Centre at Bihta industrial area. **(Source : Hindustan Times, 1.1.2015)**

पटना बनेगा सिल्क रूट का केंद्र

करीब दो हजार वर्ष पुराना सिल्क रूट फिर से शुरू होगा और इस रूट का केंद्र बनेगा पटना। चीन सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इस पर तिब्बत, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार सहित अन्य पड़ोसी देशों से बातचीत भी हो चुकी है। हांगकांग में इस रूट को लेकर नेपाल और चीन में समझौता हुआ। चीन को अब केवल भारत की सहमति का इंतजार है। सिल्क रूट को लेकर चीनी सरकार के अफसरों ने बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क किया है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर वे भारत में अगले वर्ष सेमिनार का आयोजन करने वाले हैं। चीन चाहता है कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट प्रोजेक्ट में भारत मुख्य भूमिका निभाए। इस रोड के चालू हो जाने से बिहार सिल्क उद्योग का केंद्र बनेगा ही, यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक बाजार में भारतीय सिल्क की अलग पहचान बनेगी खासकर भागलपुरी तसर, मलबरी व आर्गेनिक सिल्क की। सिल्क उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भागलपुर देश में सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से एमओयू साइन किया है।

(विस्तृतत : हिन्दुस्तान, 22.12.2014)

रेशम संस्थान का होगा कायाकल्प

राज्य सरकार भागलपुर के नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान का कायाकल्प करेगी। 1922 में स्थापित राज्य के इकलौते रेशम संस्थान में अगले शैक्षणिक सत्र से बीटेक की पढ़ाई होगी। उद्योग विभाग ने रेशम संस्थान को साढ़े तीन करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। संस्थान को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू) से संबद्धता मिलेगी। इसके लिए उद्योग मंत्री डॉ. भीम सिंह ने शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल को पत्र लिखा है।

उद्योग मंत्री डॉ. भीम सिंह ने कहा कि रेशम व वस्त्र उद्योग में तकनीकी पाठ्यक्रम तत्काल शुरू किए जाएंगे। रेशम व वस्त्र उद्योग में राज्य में एक भी उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं हैं, जिससे नौजवानों को इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। संस्थान में जान फूंकने के लिए तत्काल साढ़े तीन करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और जितनी राशि जरूरी होगी, दी जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशभर में छह मेगा क्लस्टर की घोषणा की है, इसमें भागलपुर भी एक है। रेशम संस्थान में बीटेक शुरू हो जाने से इस मेगा क्लस्टर को तकनीकी सपोर्ट मिल जाएगा। बुनकरों को लाभ होगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.1.2015)**

जमीन का 1995 से अब तक का ब्योरा होगा ऑनलाइन

जिला निबंधन कार्यालय नये साल में 1995 से लेकर अब तक के तमाम दस्तावेज को ऑनलाइन करेगा। दस्तावेज की स्कैनिंग पूरी हो गयी है। वेबसाइट पर अपलोड करने का काम जारी है। जिला निबंधन कार्यालय में काफी पुराने दस्तावेज हैं, जो उचित रख रखाव के अभाव में खराब हो रहे हैं। दस्तावेजों के स्कैनिंग की प्रक्रिया लगभग चार साल से जारी है। दिल्ली की सीबीएसएल एजेंसी (कैपिटल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) 2010 से डाटा इंट्री का काम रही है। ऑनलाइन होने से जनीन किसके नाम से है। कितनी बार बेची गयी। खरीदार कौन है? सभी जानकारी मिल सकेगी।

पुराने दस्तावेज की भी मिलेगी जानकारी : जिला अवर निबंधक प्रशांत कुमार ने बताया कि लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से इस काम को पूरा किया गया है। शीध्र ही 1960 के दस्तावेजों की स्कैनिंग होगी। प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। अनुमति मिलते ही इसका काम शुरू होगा। पटना एक मात्र ऐसा जिला है। जहाँ

पुराने दस्तावेज को ऑनलाइन किया जा रहा है। 2005 से बिहार के सभी जिलों के दस्तावेज ऑनलाइन है।

क्या होगा फायदा : • फर्जी रजिस्ट्री पर रोक • जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी • खाता व प्लॉट नंबर डालते ही दिखेगा पूरा ब्योरा • समय की बचत

(साभार : प्रभात खबर, 2.1.2015)

बिहार को मिली चार ट्रेन पटना होकर जाएगी एक

बिहार को चार ट्रेनें मिली। यह सभी ट्रेनें रेलवे बजट में घोषित की गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आनंद विहार से पश्चिम बंगाल के लिए दो और सहरसा के लिए एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें एक ट्रेन मालदा-आनंद विहार साप्ताहिक पटना होकर चलेगी। वहीं छपरा से मंडुवाडीह के लिए भी डेमू ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.1.2015)**

यूपीएस व इनवर्टर पर भी उद्यमियों को अनुदान

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैप्टिव पावर जेनरेशन, डीजी सेट के प्लांट और मशीन के साथ यूपीएस और इनवर्टर पर भी पूंजीगत अनुदान देगी। इससे बिजली की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी। लेकिन अगर बिना बिजली कनेक्शन लिए डीजी सेट और कैप्टिव पावर की मदद से कोई कंपनी उत्पादन करती है तो उसके लोड को नापने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। नए फैसले के अनुसार जमीन लेकर तय समय में उत्पादन नहीं शुरू करने वाली कंपनियों को जमीन का कन्वर्जन शुल्क देना होगा। जमीन देते समय ही इसके लिए उन्हें बैंक गारंटी देनी होगी। अगर समय पर उत्पादन नहीं शुरू हुआ तो पैसा सरकार उसी गारंटी से वसूलेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.12.2014)**

ढाई हजार नए कौशल विकास केंद्र स्थापित होंगे : रूडी

केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश में करीब ढाई हजार नए कौशल विकस केंद्र स्थापित किए जायेंगे। फिलहाल 12 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

इन युवाओं के छह माह के प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी औसतन 10-12 हजार रुपए खर्च किए जायेंगे। अनुमान है कि देश में स्किल डेवलपमेंट के 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में रूडी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि देशभर में आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों की नई श्रृंखला स्थापित की जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.1.2015)

लघु उद्योगों से 20 फीसदी खरीद एक अप्रैल से अनिवार्य होगी

सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष से सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों सहित समस्त सरकारी खरीद में इन उद्योगों से 20 फीसदी खरीद करना अनिवार्य हो जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को यहाँ बताया कि सरकार का उद्देश्य समाज के निचले स्तर के वर्गों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। **(सभार : दैनिक भास्कर, 6.1.2015)**

योजना नहीं, अब नीति आयोग

पैंसठ साल पुराना योजना आयोग इतिहास बन गया। इसकी जगह 'नीति आयोग' (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) ने ले ली। यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बौद्धिक संस्थान के तौर पर काम करेगी। आयोग का मुख्य ध्येय कारगार शासन व्यवस्था के लिए नये-नये विचारों की पौधशाला के रूप में काम करना होगा। इसका उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के संबंध में साझा दृष्टि तैयार करना है।

ऐसा होगा स्वरूप : अध्यक्ष : प्रधानमंत्री • **संचालन परिषद :** राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल • **क्षेत्रीय परिषद :** आवश्यकतानुरूप होगा गठन, इसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होंगे

सदस्य : अल्पकालिक सदस्य : अधिकतम दो सदस्य, प्रासंगिक संस्थाओं से होंगे, जो बदलते रहेंगे • **पदेन सदस्य :** केंद्रीय मंत्रिमंडल से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जायेंगे • **विशेष आमंत्रित सदस्य :** विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ • **मुख्य कार्यकारी अधिकारी :** सचिव रैंक के किसी अधिकारी को प्रधानमंत्री नियत कार्यकाल के लिए नियुक्त करेंगे • **सचिवालय :** आवश्यक होने पर होगा विचार • **कार्यालय :** संसद भवन से कुछ कदम की दूरी पर स्थित पुराने योजना आयोग के मुख्यालय भवन में ।

नयी संस्था के कार्य : • प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को 'राष्ट्रीय एजेंडा' का प्रारूप उपलब्ध करना • सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना • ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और उच्च स्तर पर पहुंचाना • समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, जहाँ योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचता • आयोग को सौंपे गये क्षेत्रों की आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को शामिल करना • रणनीतिक और दीर्घ अवधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम ढाँचा तैयार करना और पहल करना। उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार सुझाना • महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारावाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देना • राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों वे अन्य हितधारकों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना • विकास के एजेंडा को आगे बढाने के लिए अंतरक्षेत्रीय और अंतरविभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराना • अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना। जो सुशासन तथा सतत व न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने और हितधारकों तक जानकारी पहुँचाने में मदद करना • आवश्यक संसाधनों की पहचान करने, कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी, ताकि सेवा देने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके • कार्यक्रमों, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण पर जोर • राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 2.1.2015)**

जमीन की मापी पूरी, अब आर ब्लॉक से दीघा फोरलेन का काम होगा शुरू

आर ब्लॉक-दीघा रेलवे लाइन की जमीन की मापी का काम पूरा हो चुका है। अब रेलवे लाइन की जमीन पर फोरलेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उच्चस्तरीय सहमति के बाद रेलवे ने जमीन की पहले मापी कराई। उस जमीन के वैल्यूशन के बाद कीमत 1024 करोड़ लगाई गई है। मापी और वैल्यूएशन का प्रपोजल पटना डीएम को भेजा गया है। डीएम कार्यालय में एक छह सदस्यीय कमेटी बनी है। जो यह तय करेगी कि रेलवे लाइन की जमीन की वास्तविक कीमत कितनी होनी चाहिए। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ अरविंद कुमार रजक के अनुसार, सारे बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद रेलवे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को लिखेगी।

(विस्तृतः दैनिक भास्कर, 6.1.2015)

52 ग्रामीण कृषि व्यापार केंद्रों की होगी स्थापना

बिहार सरकार ने ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्रामीण कृषि व्यापार केंद्र (आरएबीसी) योजना में फिर से जान फूंकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने अब 52 नए केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। साथ ही, राज्य सरकार ने बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन को फ्री-होल्ड करने को मंजुरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इन मामलों सहित कुल 18 एजेंडों को अपनी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव बी. प्रधान ने कहा, 'राज्य सरकार ने आवास बोर्ड की जमीन और फ्लैट को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया है। इससे आवास बोर्ड से जमीन या फ्लैट लेने वाले लोग इन परिसंपत्तियों को खरीद बेच सकेंगे। इससे भारी तादाद में लोगों को फायदा होगा। आवास बोर्ड पर कानूनी खर्च का बोझ भी कम होगा।

राज्य सरकार ने बिहार में ग्रामीण और कृषि उद्योग से संबधित 52 नए व्यापार केंद्र भी स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में गोदाम, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने वाले निवेशकों को अनुदान देगी।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.1.2015)

Investment promotion bid

A committee, headed by principal health secretary Brajesh Mehrotra, would soon give a presentation before the development commissioner on the soon-to-be-launched state health investment promotion policy.

Sources in the health department confirmed that the department, along with the members of Bihar Chamber of commerce and Industries (BCCI), Bihar Industries Association (BIA), Confederation of Indian Industry (CII), has already formulated the draft of the policy, which is aimed at attracting private investment to the health sector in the state. But the presentation, which would be held before the development commissioner would decide about the changes to be brought in the draft of the policy.

Anil Kumar, the deputy secretary of the health department, confirmed the development. "The meeting will be held soon. I won' t be able to tell you about the policy draft because it is confidential, " he said.

(Details : The Telegraph, 5.1.2015)

हमारी गैस सब्सिडी पर भी 4 रु. टैक्स लेगी बिहार सरकार

कैश सब्सिडी लेने वाले उपभोक्तों को गैस सिलेंडर करीब 4 रुपए महंगा मिलेगा। कारण यह है कि हमारे खाते में आने वाले सब्सिडी के पैसे पर भी बिहार सरकार 1 प्रतिशत वैट वसूलेगी।

अभी राज्य में प्रति सिलेंडर रसोई गैस की कीमत 430 से 445 रुपए तक है। डीबीटीएल स्कीम के तहत सिलेंडर की कीमत 810 रुपए से लेकर 825 रुपए तक है। रसोई गैस पर एक फीसदी वैट देय है। इस तरह योजना से पहले गैस उपभोक्ता को प्रति सिलेंडर 4.30 से 4.45 रुपए वैट देना पड़ता था। जबकि एक जनवरी से लागू डीबीटीएल के तहत अब उपभोक्ता को 8.10 रुपया और 8.25 रुपए वैट देना पड़ेगा। यानी प्रति सिलेंडर 4 रुपए अधिक उपभोक्ताओं को देना होगा।

एक करोड़ कमाएगी सरकार : राज्य में तकरीबन 40 लाख उपभोक्ता हैं और इसमें से 60 फीसदी उपभोक्ता प्रत्येक महीने गैस सिलेंडर लेते हैं। यानी 25 लाख सिलेंडर। प्रति सिलेंडर 4 रुपए की दर से हमारी सब्सिडी पर वैट लगाकर सरकार हर माह एक करोड़ कमाई करेगी।

ये राज्य नहीं वसूलेंगे वैट : केरल, हिमाचल और पुडुचेरी ने फैसला किया है कि वे 12 सिलेंडरों की खाते में आने वाली सब्सिडी पर वैट नहीं वसूलेंगे।

....लेकिन हमारे मंत्री ने कहा : "गैस सब्सिडी पर वैट में छूट देने का प्रस्ताव विभाग के पास नहीं आया है। सरकार अगर इस पर कोई निर्णय करेगी तो देखा जाएगा।" – **विजेंद्र प्रसाद यादव**, वित्त मंत्री **(साभार: दैनिक भास्कर, 3.1.2015)**

उपभोक्ताओं की शिकायतें उठाएंगे सुविधा केंद्र

उपभोक्ताओं को कई तरह की सेवाएं देने के लिए सरकार देश के एक दर्जन से अधिक शहरों में ग्राहक सुविधा केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। अधिकारिक विज्ञाप्ति में कहा गया है कि हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग ने पंजीकृत एवं पात्र उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों से ऐसे केंद्र स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इन ग्राहक सुविधा केंद्रों की स्थापना नई दिल्ली, लखनऊ, चडीगढ़, बेंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, पूणे, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता, गुवाहटी, शिलांग, रायपुर और भोपाल में की जाएगी। ग्राहक सुविधा केंद्र उपभोक्ताओं को शिकायतों के बारे में उचित परामर्श देगा और शिकायतों को उपभोक्ता मंच में दर्ज कराने में मदद करेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 27.12.2014)**

करबिगाया परिसर को चकाचक करने की तैयारी

पटना जंक्शन के काबिगहिया रेल परिसर का दिन जल्द ही बहुरने वाला है। परिसर से अवैध दुकानें हटेंगी। नए परिसर में दो मंजिले डीलक्स शौचालय बनाए जाएंगे। परिसर को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री का निर्माण किया जाएगा। रिटायरिंग रूम का भी निर्माण किया जाएगा।

परिचालन में सुधार नए जीएम के लिए चुनौती : भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा 1978 बैच के अधिकारी एके मितल ने बुधवार को पूर्व मध्य रेल के नए जीएम का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले वे मध्य रेलवे, मुंबई में प्रमुख मुख्य इंजीनियर के पद पर रहे हैं। पूमरे जोएम के सामने तात्कालिक चुनौती पाटलिपुत्र जंक्शन के उद्घाटन की है। यह स्टेशन पिछले डेढ़ साल से उद्घाटन की बाट जोह रहा है। साथ ही दीघा रेल सह सड़क पुल और मुंगेर रेल सह सड़ल पुल की बाधाओं को दूर करने की चुनौती भी जीएम के सामने होगी।

"विभिन्न रेल मंडलों में विशेष रूप से दानापुर रेल मंडल में ट्रेनों की लेटलतीफी की दशा सुधारने का जिम्मा रेल महाप्रबंधक पर होगा।

– **ए. के. मित्तल,** महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.1.2015)**

22 लाख से ज्यादा स्वयंसेवी संगठन

सीबीआई ने देश में स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओं) की बड़ी संख्या को लेकर गंभीर सवाल उठाये हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि अलग-अलग राज्यों को मिला कर देश में 22 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं।

टॉप 10 राज्य

उत्तर प्रदेश	5.48 लाख	पंजाब	84,752 लाख
महाराष्ट्र	5.18 लाख	उत्तराखड	62,632 लाख
केरल	3.69 लाख	गुजरात	61,959 लाख
राजस्थान	1.36 लाख	बिहार	33.781 लाख
पश्चिम बंगाल	2.34 लाख	झारखंड	23,970 लाख
असम	97.437 लाख		

(साभार : प्रभात खबर, 7.1.2015)

पुराने वाहन में भी लगेगा हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट

यदि आपने अपना वाहन 2009 के बाद खरीदा है। आपके पास रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का है और उसका नंबर बीआर 01 बीएफ 1500 से आगे शुरू होता है, तो आप अपने वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एचएसएनपी) लगवा सकते हैं। परिवहन विभाग के कार्यालय में आप पहुंच कर बहुत आसानी से अपने वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर लगवा सकते हैं। परिवहन विभाग के निर्देश में काम करनेवाली एजेंसी लिंक प्वाइंट ने भीड़ को देखते हुए पटना के अपने तीन सेंटरों पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। इससे नम्बर प्लेट जल्दी इश्यू हो रहा है। नयी गाड़ियों में तो एचएनएसपी लगा कर दिया जा रहा है। लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों को नंबर लगाने को लेकर काफी सवाल थे। जिसे अब परिवहन विभाग ने हल कर दिया है। 2009 के पहले के वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। **(साभार : प्रभात खबर, 7.1.2015)**

निर्माण मजदूरों का निबंधन अब विकास मित्र कराएंगे

श्रम संसाधन विभाग ने बनाया प्रस्ताव, जल्द कैबिनेट से मिलेगी स्वीकृति

नए साल में सरकार निर्माण मजदूरों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। उन्हें अब निबंधन के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। विकास मित्र उनके घर जाकर निबंधन फार्म भरवा लेंगे। श्रम संसाधन विभाव ने इस साल मार्च-अप्रैल तक 16 लाख से अधिक निर्माण मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य रखा है। विकास मित्रों से निर्माण मजदूरों का निबंधन कराने पर सीएम भी सहमत हैं। जल्द ही श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी।

निर्माण मजदूरों को लाभ : • भवन निर्माण मरम्मत, औजार व साइकिल खरीदने के लिए 15 हजार रुपए दिया जाता है। इस राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। • बोर्ड से पंजीकृत सभी निर्माण मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ • महिला कामगार को मातृत्व लाभ के लिए दो हजार रुपए • विवाह सहायता पांच हजार रुपए • प्राकृतिक मृत्यु पर 30 हजार व दुर्घटना में मौत पर एक लाख रुपए • दाह संस्कार के लिए तीन हजार रुपए • पेंशन, परिवार पेंशन व विकलांगाता पेंशन का लाभ। **(सभार : दैनिक भास्कर, 2.1.2015)**

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296